>

Title: Need to ensure procurement of agricultural produce from farmers at the Minimum support Price - Laid

श्री ओम बिरला (कोटा): सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 50 से 90 प्रतिशत बढ़ाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है । न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य-योजना बनाने की जरूरत है । ताकि जो भी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने आये और उसकी खरीद की गारंटी सुनिश्चित हो । समर्थन मूल्य में खरीद के समय खरीद एजेंसियों के द्वारा मापदण्ड के नाम पर किसान की उपज को नहीं खरीदा जाता । सरकार को मापदण्ड में शिथिलता भी देनी चाहिए ।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो और किसानों की उपज की खरीद की गारंटी देनी चाहिए और अधिकतम किसानों की उपज को खरीदा जा सके जिससे कि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके ।